



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]  
No. 50]नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2007/पौष 27, 1928  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2007/PAUSA 27, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2007

सं. 41(आरई-2006)/2004-2009

का.आ. 51(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 1.3 के साथ पटित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 (07-04-2006 तक अद्यतन) में निम्नलिखित संशोधन करती है :

1. पैरा 3.10.5 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा:—

“ईडीआई पोत लदान 3.10.6

स्कीम के तहत हकदारी उन सभी पोत लदानों को मंजूर की जायेगी जिनका निर्यात सीमा-शुल्क ईडी आई समर्थित पत्तनों के माध्यम से किया गया है।”

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/423/एम 07/पीसी-1]

भवानी सिंह मीना, विदेश व्यापार महानिदेशालय  
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2007

No. 41 (RE-2006)/2004—2009

S. O. 51(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, as amended, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy, 2004—2009 (Updated as on 07-04-2006):

1. After the Para 3.10.5, the following para shall be inserted:—

“EDI Shipments 3.10.6

The entitlement under the scheme shall be granted to all shipments that are exported through Customs EDI enabled ports.”

This issues in Public interest.

[F. No. 01/94/180/423/AM07/PC-1]

B. S. MEENA, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.